राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1334/2022

विकास पुत्र श्री रक्मा, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी बादली खेड़ा पी. एस. गनताली जिला प्रतापगढ़। (वर्तमान में जिला जेल, प्रतापगढ़ में)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य , अभियोजक द्वारा

2. नारायण पुत्र श्री मंगला भील, आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी बिलादिया, पिनपलखूंट जिला प्रतापगढ़।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री कालू राम भाटी

उत्तरदाता(गण) के लिए : -

न्यायाधिपति श्री फरजन्द अली

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

<u>05/12/2022</u>

विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम प्रकरण, प्रतापगढ़ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 113/2022 में पारित आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्य, जो कि पुलिस स्टेशन पीपलखूंट की प्राथमिकी संख्या 76/2002 से उत्पन्न हुआ है, को आरोपी-याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आपराधिक संशोधन याचिका दायर करके चुनौती दी गई है।

इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस निजी उत्तरदाताओं को विधिवत तामील करा दिया गया है; जिसका सबूत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है, जिसके अनुसार, एस.एच.ओ., पी.एस. पीपलखूंट ने शिकायतकर्ता को तत्काल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के संबंध में सूचित किया।

विस्तृत विवरणों के अभाव में, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 (1) और POCSO अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराधों के लिए उपरोक्त एफआईआर के संबंध में 05.06.2022 को गिरफ्तार किया गया था।

सीआरपीसी की धारा 167 के उप-खंड (2) में निहित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आरोप-पत्र आरोपी (उसका/उसकी) की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर रिमांड के लिए संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 03.09.2022 तक, संबंधित अदालत के समक्ष कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए, अभियुक्त की ओर से आरोप-पत्र दाखिल न करने के आधार पर निचली अदालत में डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2022 को किए गए डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन और समर्थन की एक प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। अनुमोदन से यह पता चल रहा है कि डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन दाखिल करने पर, विद्वान न्यायाधीश ने कार्यालय द्वारा चेक-रिपोर्ट तैयार करने के बाद मामले को 07.09.2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इस मामले में आरोप पत्र 06.09.2022 को दायर किया गया था, यानी आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिन की समाप्ति के बाद और डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने के बाद भी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***उदय मोहन लाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1910*** के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में चूक के कारण जमानत पर रिहा होने का अभियुक्त का अधिकार एक मूल्यवान और

अपरिहार्य अधिकार है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दोहराया गया है और इसी सिद्धांत को बार-बार दोहराया गया है।

विद्वत विचारण न्यायालय ने जमानत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि यद्यपि जमानत आवेदन आरोप-पत्र दायर करने से पहले प्रस्तुत किया गया था, लेकिन आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत पर बहस करने को तैयार नहीं था, इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले, आरोप-पत्र 06.09.2022 पर प्रस्तुत किया गया था, इसलिए, याचिकाकर्ता का डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार आरोप-पत्र दायर करने के बाद समाप्त हो गया है। हालाँकि, रिकॉर्ड पूरी तरह से एक अलग दृश्य को दर्शाता है। निर्विवाद रूप से अभियुक्त द्वारा डिफॉल्ट जमानत आवेदन दिनांक 03.09.2022 को दाखिल किया गया था। जमानत आवेदन पर अदालत द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया था कि आरोपी की ओर से कोई स्थगन मांगा गया था, हालाँकि, अदालत ने मामले को 07.09.2022 पर जमानत याचिका की सुनवाई के लिए पोस्ट किया और इस बीच, आरोप-पत्र 06.09.2022 पर प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अभियुक्त के कारण को विफल करने के उद्देश्य से, जमानत आवेदन की सुनवाई स्थगित कर दी गई थी और इसे 07.09.2022 पर

सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था ताकि एजेंसी इस बीच आरोप-पत्र दायर कर सके। यह कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं होता है कि अभियुक्त जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक और तैयार नहीं था।

आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियुक्त जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार था और इच्छुक था, इस प्रकार, अदालत पर जमानत बांड प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश पारित करना अनिवार्य था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। इस प्रथा की सराहना नहीं की जा सकती है कि जब कोई आरोपी वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद आरोप-पत्र दाखिल न करने के आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करता है, तो अदालत एजेंसी को इस बीच आरोप-पत्र दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जमानत याचिका पर सुनवाई टाल देती है।

(2020) 10 एस. सी. सी. 616 में रिपोर्ट किए गए ***बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य*** के मामले में दिए गए फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने "यदि पहले से ही लाभ नहीं उठाया है" अभिव्यक्ति को निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया है:"

इसके बाद अदालत ने कहाः

"13.... इसलिए, विचार के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि "यदि पहले से ही उपयोग नहीं किया गया है" अभिव्यक्ति का सही अर्थ क्या है?क्या इसका मतलब यह है कि कोई आरोपी जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानत पर रिहा होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है या इसका मतलब यह है कि जमानत का आदेश पारित किया जाना चाहिए, आरोपी को जमानत देनी होगी और उसे जमानत पर रिहा करना होगा? हमारी सुविचारित राय में यह विधायी जनादेश के अनुरूप होगा कि एक आरोपी को अपने अपरिहार्य अधिकार का लाभ उठाने के लिए अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए, **जिस क्षण वह जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन दायर करता है और जमानत के नियमों और शर्तों का पालन करने की पेशकश करता है।**

आवश्यक जमानत देने के बाद वास्तव में जमानत पर रिहा होने के अर्थ में "लाभ उठाया" शब्द की व्याख्या करने से आरोपी के साथ बहुत अन्याय होगा और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के परंतुक के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा और इसके

अलावा अवैध हिरासत को कानूनी बना दिया जाएगा, क्योंकि निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद मजिस्ट्रेट के पास रिमांड का कोई और अधिकार क्षेत्र नहीं है और आरोपी की ऐसी हिरासत रिमांड के किसी भी वैध आदेश के बिना है। इसके अलावा, जब कोई अभियुक्त जमानत के लिए आवेदन दायर करता है जो निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई चालान दायर नहीं किए जाने के कारण रिहा होने के अपने अधिकार का संकेत देता है, तो मजिस्ट्रेट के पास कोई विवेकाधिकार नहीं बचा है और उसे केवल यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि बीत चुकी है या नहीं, और क्या चालान दायर किया गया है या नहीं।

यदि अभिव्यक्ति "लाभ उठाया" का अर्थ यह समझा जाता है कि अभियुक्त को वास्तविक रूप से जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, तो किसी ऐसे मामले में जहां मजिस्ट्रेट धारा 167 में निर्धारित अधिकतम अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से आदेश पारित करने से इनकार कर देता है, और फिर भी कोई चालान दायर नहीं किया गया था, तो अभियुक्त केवल उच्च मंच पर जा

सकता है और जब मामला विचार के लिए उच्च मंच में लंबित रहता है, यदि अभियोजन पक्ष आरोप-पत्र दायर करता है तो जांच एजेंसी की ओर से निष्क्रियता के कारण अभियुक्त को प्राप्त तथाकथित अधिकार भी विफल हो जाएगा। चूंकि विधायिका ने अपना आदेश दे दिया है, इसलिए इसे लागू करना अदालत का परम कर्तव्य होगा और "यदि लाभ नहीं उठाया गया" अभिव्यक्ति की इस तरह से व्याख्या करके उसे नकारना न्याय के हित में नहीं होगा, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।

22. इस मामले के तथ्यों पर दूसरा परेशान करने वाला सवाल डिफ़ॉल्ट जमानत देने का सवाल है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि एक बार अपराध की जांच के लिए अधिकतम अवधि समाप्त हो जाने के बाद, धारा 167 (2) के पहले परंतुक (ए) के तहत, आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि यह संहिता द्वारा दिया गया एक अपरिहार्य अधिकार है। इस अपरिहार्य अधिकार की सीमा कई निर्णयों का विषय रही है। **हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 602** के फैसले से शुरुआत की जा सकती है, जिसमें आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (इसके बाद

"टाडा" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत "डिफ़ॉल्ट जमानत" की बात की गई है, जिसे संहिता की धारा 167 के साथ निम्नानुसार पढ़ा गया हैः

> "19. टाडा की धारा 20(4) सीआरपीसी की धारा 167 को टाडा के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े मामले के संबंध में लागू करती है, जो उसमें निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन है... जबकि खंड (बी) में प्रावधान है कि धारा 167 की उप-धारा (2) में '15 दिन', '90 दिन' और '60 दिन' जहां भी वे होते हैं, उन्हें क्रमशः '60 दिन', 'एक वर्ष' और 'एक वर्ष' के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।इस धारा को 1993 में 1993 के संशोधन अधिनियम 43 द्वारा 22-5-1993 से संशोधित किया गया था और धारा 167 की उप-धारा (2) में संशोधन करके खंड (बी) में 'एक वर्ष' और 'एक वर्ष' की अवधि को घटाकर क्रमशः '180 दिन' और '180 दिन' कर दिया गया था।"

टाडा की धारा 20 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के बाद, एक और खंड (बीबी) जोड़ा गया था जिसमें कहा गया हैः

> "(ख) उप-धारा (2) में, परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः बशर्ते कि, यदि एक सौ

अस्सी दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो नामित न्यायालय लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जांच की प्रगति और एक सौ अस्सी दिनों की उक्त अवधि से परे आरोपी की हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत देते हुए उक्त अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा देगा; और

20. ...संहिता की धारा 167 की उपधारा (2) में कहा गया है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास आरोपी को भेजा गया है, वह उस धारा में निर्दिष्ट अवधि के लिए उसे हिरासत में रखने की अनुमति दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।उप-धारा (2) का परंतुक बाहरी सीमा तय करता है जिसके भीतर जांच पूरी होनी चाहिए और यदि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो आरोपी को जमानत पर रिहा होने की मांग करने का अधिकार प्राप्त होगा और यदि वह यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और देता है, तो मजिस्ट्रेट उसे जमानत पर रिहा कर देगा और ऐसी रिहाई को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXIII के तहत जमानत देना माना जाएगा...धारा 167 को टाडा की धारा 20(4) के साथ पढ़ा

जाता है, इस प्रकार, स्पष्ट रूप से कहें तो यह "जमानत देने" का प्रावधान नहीं है, बल्कि अधिकतम अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है और जांच एजेंसी को जांच पूरी करने और यदि आवश्यक हो तो अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इसलिए, टीएडीए की धारा 20(4)(बी) के साथ पढ़ी जाने वाली संहिता की धारा 167(2) का परंतुक, निर्धारित या विस्तारित अधिकतम अवधि के भीतर जांच पूरी करने में जांच एजेंसी द्वारा 'चूक' के कारण आरोपी व्यक्ति में जमानत पर रिहाई के लिए आदेश मांगने का एक अपरिहार्य अधिकार देता है। यही कारण है कि टाडा की धारा 20 (4) के साथ पठित संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के तहत जमानत पर रिहा होने के आदेश को आम तौर पर "ऑर्डर-ऑन-डिफॉल्ट" कहा जाता है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष द्वारा जांच पूरी करने और निर्धारित अवधि के भीतर चालान दायर करने में चूक के कारण दिया जाता है। संशोधन के परिणामस्वरूप, एक आरोपी अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 180 दिनों की समाप्ति के

बाद जमानत का हकदार हो जाता है, भले ही उस अपराध की प्रकृति के साथ उस पर आरोप लगाया जाता है, जहां अभियोजन पक्ष जांच पूरी होने पर उसके खिलाफ चालान पेश करने में विफल रहता है। सीआरपीसी की धारा 167 की उपधारा (2) के परंतुक के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (बी) में संशोधन के साथ, आरोपी के पक्ष में जमानत पर बढ़ाए जाने का एक अपरिहार्य अधिकार अर्जित होता है यदि पुलिस जांच पूरी करने और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ चालान पेश करने में विफल रही। **ऐसे मामले में, अदालत पर एक दायित्व डाला जाता है, जब अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद, जिसके दौरान एक आरोपी को हिरासत में रखा जा सकता है, धारा 20(4) के खंड (बीबी) द्वारा शासित मामलों को छोड़कर, आगे के रिमांड के लिए पुलिस के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है। एक और दायित्व भी है जो अदालत पर डाला जाता है और वह है अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करना और उसे उस ओर से आवेदन करने में सक्षम बनाना।** (हुसैनारा खातून मामला [हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, (1980)

1 एस. सी. सी. 98:1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 40: ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1369])। इस कानूनी स्थिति को असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1992) 4 एस. सी. सी. 272:1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 870: ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1] में बहुत कुशलता से कहा गया है, जहां बहुमत के लिए बोलते हुए, न्यायमूर्ति अहमदी ने रजनीकांत जीवनलाल पटेल बनाम खुफिया अधिकारी, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली [(1989) 3 एस. सी. सी. 532:1989 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 612: ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 71] में निर्धारित कानून को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः (एससीसी पृष्ठ 288, पैरा 9) "धारा 167(2) परंतुक (ए) के तहत जमानत का अधिकार पूर्ण है। यह एक विधायी आदेश है न कि अदालत का विवेकाधिकार। यदि जाँच एजेंसी 90/60 दिनों की समाप्ति से पहले आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है, तो हिरासत में आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।लेकिन उस स्तर पर, मामले के गुण-दोष की जांच नहीं की जानी चाहिए, बिलकुल

नहीं। **वास्तव में, मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति को 90/60 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे रिमांड करने की कोई शक्ति नहीं है। उसे जमानत का आदेश पारित करना होगा और अपेक्षित जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए आरोपी को इसकी सूचना देनी होगी।"**

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन या जैसा भी मामला हो, की उक्त अवधि की समाप्ति पर, निर्धारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र प्रस्तुत न करने पर जांच एजेंसी द्वारा अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने के लिए एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त होता है और अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार है, यदि वह जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। पूर्वनिर्धारित जमानत आवेदन को आगे बढ़ाने की तैयारी, इच्छा और उसके इरादे को उस समय से एकत्र किया जा सकता है जब वह पूर्वनिर्धारित जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन दायर करता है। बेशक, यह अदालत का काम है कि वह मुचलके और जमानत बांड की राशि और शर्तों को पूरा करने पर उसकी रिहाई का एक स्पष्ट आदेश पारित करे। न तो एजेंसी और न ही अदालत इस आधार पर उपरोक्त शर्त का लाभ उठा सकती है कि डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन की

सुनवाई करने और उस पर आदेश पारित करने से पहले, आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान मामले में, मेरे सुविचारित विचार में, डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन की सुनवाई के बाद आदेश पारित नहीं करने और इस बीच आरोप-पत्र दायर करने के लिए एजेंसी को आमंत्रित करने का कार्य अभियुक्त-याचिकाकर्ता के उद्देश्य को पराजित करने और विफल करने का प्रयास है। यह अदालत अनेक न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों द्वारा उपयुक्त रूप से निर्देशित है और उसका मानना है कि इस मामले के आरोपी ने डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था और डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर करके उसका इरादा और तैयारी दिखाई गई है और निचली अदालत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन पर एक उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक संशोधन याचिका सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम मामले, प्रतापगढ़ द्वारा जमानत आवेदन संख्या.113/2022 में पारित दिनांकित 07.09.2022 आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। अभियुक्त को विद्वत विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए Rs.50,000/- की राशि में दो प्रतिभूतियों के साथ

Rs.25,000/- की राशि में व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश विषय आरोप के संबंध में अन्य वैध और ठोस कारणों पर आरोपी-याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी/पुनः गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाता है या अन्यथा रोकता नहीं है। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में, वह नियमित जमानत के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस पर मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(न्यायाधिपति फरजंद अली)

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।